Expert of Alumina by NALCO

*138. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA; Will the Minister of COMMERCE , be pleased to state;

(a) whether it fe a fact that NALCO is exporting Alumina through MMTC losing 50 dollars per ton on an average-On. ' the basis of the existing international price and that the estimated loss of ,15 million' dollars on the commodity is anticipated in the" current year alone;

(b) if- so, what are the details thereof stating the reasons for such' a huge loss; and

(c) wtoat steps government propose to take *to* minimise the loss?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) to- (c) MMTC signed a Memorandum of Undestandjng (MOU) in consultation with National. .Aluminium Company (NALCO) with M|s. Hydro Trading SA Lausanne Switzerland on 20-3-1987 for export of 100,000 tonnes" of Alumina at a minimum, price of US. 126 PMT FOB and 10.5 per cent ou ,average cash London Metal Exchange (LME) price of aluminium for the month prior to the month of . shipment. -The MOU provided for detailed contract to be finalised by April, 1987. This being the first, contract for export of alumina through MMTC, it took some time to * finalise the terms of the contract, draff of which could be forwarded by MMTC to M|s. Hydro Trading in May, 1987. The foreign buyers raised some objec- . tions. After discussion between NALCO; MMTC and Hydro Trading, a contract Was finalised, in November, 1987 stipulating export of 100,000 tonnes of alumina at a price of US $ 160 PMT FOB. The contract wag finalised atiruling in-ternational market price, The .arrange*-ment^was made by these organisations on over all commercial considerations.

Signing of memorandum of understanding with the *Swiss* Authorities

139.SHRI KAILASH PATI MISHRA:

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

Will the Minister of FINANCE be' _pleased to state:.

(a) whether Government had- initiated steps -to.enter into a Memorandum of Understanding with the Swiss authorities for-assistance in specific cases of Indians having accounts in Swiss banks with fund$ obtained illegally if so, by when;

<b) whether it is a fact that a «ix member, team pf officials of .various Ministries,-visited Switzerland in this regard and submitted its report in October last;

"(c) what further communications have taken place during these months "with the Swiss Government; and

(d) what sort of agreement|understand-ing is going to be signed between the . two countries and by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AF-FAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO);

(a) to (d) A' team comprising representatives of -Department of Economic Affairs, Ministry Of External Affairs, Central Bureau of investigation and the Reserve Bank of India visited Berne (Switzerland) in September, 1987, to explore the J»- -. sibilities of entering into an arrangement . for**riutual assistance 'in criminal" matters between the Governments of India and Switzerland. Based on the recommendations of the team, Government is exploring the feasibility of exchange Of letters between the two governments for mutual asssistance in criminal matters.

Investment in canshare and canstocfc

»140. SHRI K. MOHANAN; Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have given*-their concurrencevin favour of Non-resident Indians* investment in Canshare *iai* Canstock; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT. OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALIERO):
(a) Y?s, Sir.

(b) Government have permitted Non-Resident Indians' investment in Canshare Md Canstock on non-repatriable basis.

सूखा प्रभावित राज्यों के लिये केन्द्रीय सहायता

@728. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रभावित राज्यों को कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता/सहायता अनुदान किन-किन शर्तों पर प्रदान की गई;

(ख) क्या इन राज्यों को केन्द्रीय सहायता के भुगतान से इन राज्यों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार आने की सम्भावना है, और यदि हां, तो इस खर्च को किस प्रकार पूरा किया जायेगा; और

(ग) इस संबंध में राज्यों की क्या-क्या मांगें हैं?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) वर्ष 1987–88 के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों को 1113.55 करोड़ रुपये की अग्रिम योजनागत सहायता तथा 74.96 करोड़ रुपये की सीमान्त राशि प्रदान की गयी है। जहां तक प्रदान की गई सहायता की शर्तों का संबंध है विवरण–I संलग्न है। (नीचे देखिये)

(ख) केन्द्रीय सहायता सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में चालू सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए, नगर जल-आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने/उनके कार्य में तेजी लाने तथा ऐसे लाभ कर उत्पादी रोजगार के लिए प्रदान की गयी है, जो भविष्य में इस प्रकार के व्यय की आवश्यकता को दूर करेगी चुनिन्दा सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए किये जा रहे अतिरिक्त व्यय सिंचाई की क्षमता और पोषणिक अनुपूर्ति को बढ़ाएगा तथा कृषि पैदावार बढ़ेगी। सूखा सहायता पोषणिक अनुपूर्ति, स्वास्थ्य उपायों, पशुओं के लिए चारा, बीज सहायता आदि के लिए भी प्रदान की गयी है जिससे सूखे की परिस्थितियों के बावजूद भी उत्पादन क्षमता का परिरक्षण और पोषण होगा।

सूखा राहत पर किया गया व्यय अतिरिक्त संसाधन जुटाकर तथा व्यय में किफायत करके केन्द्र तथा राज्यों के राजस्व से पूरा किया जा रहा है।

(ग) विवरण–II संलग्न है।

विवरण–I

सूखे के मामले में राज्य सरकार द्वारा अपने सीमान्त धन से अधिक तथा संबंधित वर्ष के लिए अपने वार्षिक योजनागत परिव्यय के 5% तक किया गया व्यय, उस वर्ष में योजनागत परिव्यय से अतिरिक्त माना जाता है और इसे अग्रिम योजनागत सहायता में शामिल किया जाता है। अग्रिम योजना सहायता विशेष श्रेणी के राज्यों को 10% ऋण तथा 90% अनुदान के रूप में और गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों को 70% ऋण तथा 30% अनुदान के रूप में दी जाती है। यह अग्रिम योजनागत सहायता सूखे की समाप्ति के पश्चात् अगले पांच वर्षों के अन्दर राज्य की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के प्रति समायोजित की जाती है। जहां पर ऐसा व्यय वार्षिक योजनागत परिव्यय से 5% से अधिक होता है, इसे विपदा की असाधारण प्रचण्डता के रूप में लिया जाता है तथा अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 423, 28 अप्रैल, 1988 से स्थानांतरित।